

जल संसाधन मंत्री ने बांध सुरक्षा पर राज्यों के मंत्रियों की कार्यशाला में रखा बिहार का पक्ष

## बाढ़ से सुरक्षा को नेपाल में बने हाईडैम : संजय

फरक्का बराज के कारण गंगा में है गाद की समस्या

सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को जल्द अंतिम रूप दे केंद्र

इंद्रपुरी जलाशय जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों पर प्रगति के लिए पहल करे केंद्र

### पटना/विशेष संवाददाता

बिहार जो सोचता है, देश उसे बाद में अमल करता है। बिहार सरकार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने ग्रहण करते हुए इसे राज्यों को अमल करने की नसीहत दी है। नागरिक सुविधाओं से जुड़ी ऐसी योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। बाढ़ से होनेवाले नुकसान और जानमाल की क्षति रोकने के लिए बांध की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों की सहभागिता से पहल शुरू कर दी है। बिहार इसमें भी आगे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की बागडोर नवंबर 2005 में संभालने के तुरंत



जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा से मोमेंटो प्रदान करते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

### केंद्रीय मंत्री को रबर डैम देखने का दिया न्योता

पटना। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने गया में बिहार सरकार की 'रबर डैम' बनाने की अनूठी पहल को देखने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को बिहार आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना के अनुरूप गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट बिहार का पहला रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इससे फल्गू नदी सालों भर पानी रहेगा। गया में हर साल देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। गर्मी में फल्गू नदी सूख जाने के कारण श्रद्धालुओं को नहाने-धोने और पूजा-अर्चना करने में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार यह अभिनव योजना है। इससे श्रद्धालुओं को अब पूजा-अर्चना और स्नान आदि करने में परेशानी नहीं होगी।

बाद 2006 में बांध सुरक्षा अधिनियम बनाया और बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पुनः बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने बिहार की लंबित मांग को पुनः उठाते हुए बाढ़ से सुरक्षा के लिए कोसी के निकट नेपाल में हाईडैम बनाने की दिशा में तत्परता से पहल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया। उन्होंने कहा कि हाईडैम बनाने का अंतर्राष्ट्रीय मसला है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकार को ही इस मामले में पहल करना है। नेपाल में हाईडैम बनाने के लिए डीपीआर बनाने का मामला 2004 से ही लंबित है। 18 वर्ष गुजरने के बाद भी इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। स्थिति यह है कि पांच वर्षों से कोसी क्षेत्र में बाढ़ से निबटने और कटाव निरोधक कार्यों पर सालाना एक-एक हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। कोसी में हाईडैम **शेष पेज 11 पर**